New India Express- 24- February -2021

No fund allocation for river project dashes hopes

R SIVAKUMAR @ Vellore

VELLORE farmers have expressed disappointment over the State government's failure to allocate funds for the much-clamoured Thenpennai-Palar interlinking project in the interim Budget presented on Tuesday.

'Palar' AC Venkatesan, secretary, Coordination Committee of Tamil Nadu All Farmers Associations, said, "We expected the State government to allocate a considerable amount of money to kickstart the Thenpennai-Palar interlinking project. But the interim Budget has destroyed our hopes."

Pointing out at the condition of waterbodies in the region, particularly the Thenpennai and Palar rivers, he said, "The failure to allocate funds for the ambitious scheme showed the government's lack of interest in improving the water resources in northern parts of the State. We appreciate the government's commitment in carrying out the river interlinking and irrigation projects in the southern and western parts of the State, but it should also focus on the development of the northern regions," said Venkatesan. The general public and the farmers in these districts feel the government has ignored their interests, he rued.

'Palleri' K Raja, district president, Thamizhaga Vivasayigal Sangam, said, "The government has been making many promises on implementing the project. But its failure to allocate funds in the interim Budget proves that it has failed to live up to its words." We have been waiting for years for the interlinking project to be implemented, which would thereby save northern Tamil Nadu from falling into desertification. We are left disappointed now, he said.

Deccan Chronicle- 24- February -2021

Another TS, AP water row erupts

L. VENKAT
RAM REDDY I DC
HYDERABAD, FEB. 23

Yet another water row has erupted between Telangana and Andhra Pradesh.

The Telangana state government took a serious view of the AP government launching works to construct a canal at Rajolibanda village in Kurnool district, in parallel to the existing Rajolibanda Diversion Scheme (RDS) to draw additional water without obtaining any approvals from various government agencies. This will deny Telangana its rightful share and adversely affect the erstwhile Mahabubnagar district.

Public representatives and farmers of Gadwal and Mahabubnagar districts complained to Chief Minister K. Chandrashekar Rao that the AP government had started making markings to dig a canal on the right side of the RDS.

Official sources in the irrigation department said that Rao discussed the issue with officials on Tuesday and directed them to lodge a complaint with the Krishna River Management Board, the Central Water Commission and the Apex Council of the Union ministry of Jal Shakti against the AP government and ensure that Andhra Pradesh suspends these works.

Though TS is supposed to get 16 tmc ft of water through the RDS, it is getting less than five tmc currently due to leakages.

■ Page 2: Farmers worry about AP's parallel project

Deccan Chronicle- 24- February -2021

Farmers worry about AP's parallel project

From Page 1

Farmers complained that if AP builds a parallel canal, it would deprive Telangana of even the minimum five tmc of water.

Irrigation project RDS is located on Tungabhadra river and spread in Gadwal district of Telangana, Kurnool district of AP and Raichur district of Karnataka. It is an inter-state barrage on Tungabhadra river, which supplies water to the three states.

The RDS is crucial for Telangana, as it irrigates about 87,000 acres in the state and 4,000 acres in AP. Telangana has been allocated 15.9 tmc from the RDS but gets an average of only five tmc.

IRRIGATION PROJECT
RDS is located on Tungabhadra river and spread in Gadwal district of Telangana, Kurnool district of AP and Raichur district of Karnataka.

The RDS has only one canal, which emanates from the left side of RDS anicut on Tungabhadra river. The anicut is located at the border of Andhra Pradesh (Kurnool) and Karnataka (Raichur). The canal passes through Karnataka for 43 kms and flows into Telangana for the remaining 100 km. It is intended to serve an ayacut of 5,900 acres, utilising 1.2 tmc in Karnataka and 87,500 acres with 15.9 tmc in Telangana. The tailend reaches in Telangana have not been getting water for decades due to leakages.

RDS was one of the main issues during the Telangana statehood agitation. However, it was not addressed in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Due to this, farmers under the RDS canal in Gadwal district are still awaiting their rightful share of water to reach their fields even more than six years after Telangana state was formed.

Pioneer- 24- February -2021

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर किया आगाह

आपदा सहने वाले बुनियादी ढांचे को समय की मांग बताया

भाषा। खड़गपुर (पश्चिम बंगाल)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों और हाल ही में उत्तराखंड में हुई घटना जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति मंगलवार को आगाह करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को आपदा के प्रभावों का सामना कर सकने वाले सक्षम आधारभूत ढांचा विकसित करने को कहा। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने छात्रों को तीन आत्म (सेल्फ थ्री)-- आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निःस्वार्थ भाव-- का मंत्र दिया, ताकि वे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का स्टार्टअप (माध्यम) बन सकें। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) जैसे कार्यक्रमों के जरिए सुरक्षित, वहनीय एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की उपलब्धता की जरूरत का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हमारे आधारभूत ढांचे को नष्ट कर देती है। भारत ने दुनिया का ध्यान आपदा प्रबंधन के मुद्दे की ओर आकृष्ट किया है। आपने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड में क्या हुआ। हमें आपदा सहने में सक्षम आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को बर्दाश्त कर सके। मोदी ने आपदा सहने में सक्षम आधारभूत ढांचे पर वैश्विक गठबंधन (सीडीआरआई) का विचार किया, जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया गया था। सीडीआरआई सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्तीय ढांचे, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों का ऐसा गठजोड़ है जो जलवायु एवं आपदा खतरों को सहने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए आईआईटी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और उसकी भूमिका की सराहना की।उन्होंने कहा कि संस्थानों को अब स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी समस्याओं का भविष्योन्मुखी समाधान तलाशने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा, आप भारत के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और आकांक्षाएं भी बदल गई हैं।

अब आईआईटी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में अगले मुकाम पर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों से कहा कि जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। जैसे कि-- क्या यह रास्ता सही है, गलत है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ? प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। इन सवालों का उत्तर तीन आत्म (सेल्फ थ्री) में हैं। आप अपने सामर्थ्य को पहचानकर आगे बढ़ें, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ें। स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा की जरूरत को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सुरक्षित, वहनीय एवं पर्यावरण अनुकूल विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया।उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत उन देशों में एक है, जहां सौर ऊर्जा की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर-घर तक सौर ऊर्जा (सोलर पावर) पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। उन्होंने छात्रों से कहा, क्या आप चूल्हा उपयोग करने वाले घरों तक सोलर कुकर पहुंचा सकते हैं। मोदी ने कहा, आपने जो सोचा है, आप जिस नवाचार पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपको पूरी सफलता ना मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी प्रौद्योगिकी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, टिकाऊ हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्शे और भूस्थानिक आंकड़ों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। इस कदम से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए माहौल सुदृढ़ होगा। मोदी ने कहा, इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप और नवोन्मेषकों को नई आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा, आप सभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है।

सुजलां और सुफलां के लिए बने हिमालय मंत्रालय

राजकुमार भारद्वाज

हिमालय में हिमशैल (ग्लेशियर) के टूटने से उत्तराखंड में भारी विपदा आई। चमोली में जहां यह त्रासदी हुई, उसकी दूरी रैणी गांव से 20 किलोमीटर भी नहीं है। रैणी वही गांव है, जहां की गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का श्रीगणेश किया था।

गौरा देवी अपने गांव की महिलाओं के साथ वृक्ष से चिपक गई थीं। उन्होंने जंगल के ठेकेदारों से खुला टकराव लिया था और कहा था- पेड़ नहीं कटने देंगे, मुझे गोली मारो। रैणी और आसपास के लोग इस परियोजना से संभावित खतरों की चर्चा भी नियमित कर रहे हैं कि प्रकृति के संसाधनों का किस सीमा तक दोहन किया जाए और पर्वतराज हिमालय के संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाएं। पहाड़ की समस्याओं के समाधान टर्नकी प्रोजेक्टर करने वाले बड़े इंजीनियरों के बजाय, यहां बसने वाले नागरिकों के पास अधिक सरल और शीघ्र हैं, क्योंकि पीढ़ियों से वे यहां रहते आए हैं और जन्म-जन्मांतरों का अनुभव उनके खून में घुला-मिला है।

जड़ों से नदी को काटकर उस पर जलविद्युत परियोजनाओं का क्या प्रयोजन है? उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर, जंगल और तलहटी नदी के बनने के क्षेत्र होते हैं। यदि इन्हें ही मिटा देंगे, तो नदी का सूखना निश्चित है। ऐसे में मृत नदी पर विद्युत योजना बनाने से अर्थ का अनर्थ ही होगा। हिमालय का इतिहास बताता है कि कई बार बड़े जलधारे बंध और मार्ग त्यागकर स्वच्छंद हो जाते हैं और बड़ी जल राशि मृत नदी में आ जाती है। ऐसे में नदी को मृत मानकर कालान्तर में जो भी निर्माण किए जाएंगे, वे भयंकर बाढ़ की सूरत में जलप्लावित हो जाएंगे।

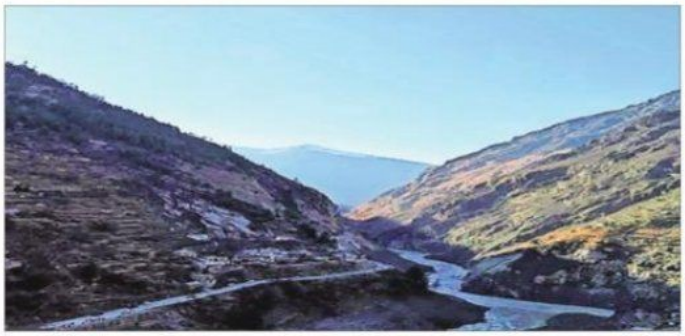

परामर्श

हिमालय की वर्तमान परिस्थितियों को बनने में हजारों साल लगे हैं, लेकिन उसे बिगाड़ने का काम हमारा समाज कुछ सालों से कर रहा है। श्रीमद् भगवद्गीता में स्वयं श्री हरि के पूर्णावतार निष्काम कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कहा है, ह्रमहर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।।

भगवान ने खुद ही कहा, 'स्थावराणां हिमालय' अर्थात स्थिर पर्वतों में मैं हिमालय हूं। हमारे पुरखों ने भी बहुत सोच-समझकर यहां बस्तियां, मंदिर और खेती आदि कार्यों व संरचनाओं को मूर्तरूप दिया। यही वजह है कि भूकम्प को छोड़कर, भारी वर्षा, हिमपात, तूफान, ओलावृष्टि और सूखे आदि बहुत सी विपदाओं के बावजूद कदीमी गांव बचे ही रहते हैं। जैसे श्री बद्रीधाम में सैकड़ों वर्षों से कई बड़े हिमस्खलन हुए, परन्तु मंदिर सदा सुरक्षित ही रहा। यह भारतीय स्थापत्य कला के दूरगामी चिंतन का द्योतक भी है, क्योंकि यह धाम सबसे सुरक्षित जगह पर स्थित है और बिना अध्ययन के ऐसे स्थान का चयन हो ही नहीं सकता। यह नारायण की कृपा भी है।

नदियों में खनन, जैव विविधता का अहित, वृक्षों का कटान और विद्युत परियोजनाएं औपनिवेशिक मानसिकता भर नहीं है। बल्कि अब हमने हिमालय को आध्यात्य की जगह सामान्य समझ और लालची दृष्टि से देखना और समझना शुरू कर दिया है, जिसमें होटल वालों को होटल, फूल वालों को फूल, पानी की बोतल वालों को बोतल, औषधि निमार्ताओं को जड़ी बूटी, जंगलों के तस्करों को जंगल की अपार संपदा, नदियों के व्यापारी को नदी का बहाव, जमीनों और जलवायु वालों को जमीनें और खनकों को खनिज संपदा का लोभ है, तो कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए हिमालय अनंत कमाई देने वाला बन गया है।

पंडित दीनदयाल ने जी आर्थिक योजनाओं के बारे में लालच के संदर्भ में स्पष्ट संकेत साझा किए हैं, 'आर्थिक पहलू पर विचार करते समय लोग मानसिक प्रवृत्तियों पर विचार नहीं करते हैं, जबकि हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर मानसिक प्रवृत्तियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रवृत्तियां सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होती हैं। अतः हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव रहता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे आर्थिक प्रयास किस आधार पर चलें, इस बात की स्पष्ट व्याख्या है, भौतिक विकास के लिए उसमें समुचित स्थान है।' पंडित जी मानसिक प्रवृत्तियों की उच्चशृंखलता के साथ भारतीय संस्कृति का भी उल्लेख करते हैं कि भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषाएं हैं, उसी के अनुरूप वर्तना चाहिए, न कि विदेशी पद्धतियों का अंधानुकरण किया जाए।

मात्र लालच, धन और आवश्यकताओं के वशीभूत होकर हम हिमालयी संपदा का दुरुपयोग करते रहे, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा हिमालय, कैसी नदियां, कैसी गंगा-यमुना, कैसे बद्री-केदार, गंगोत्री-यमुनोत्री, साज-समाज, वन-उपवन, जैव विविधता से भरपूर पहाड़ आदि अनंत महा पराशक्तियों से भरपूर देव भूमि संरक्षित रख पाएंगे।

पानी साफ करने के लिए डीडीए करेगा परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल

■ राजेश तिवारी

नई दिल्ली। एसएनबी

भूजल के स्रोतों को शुद्ध बनाने एवं गंदे पानी को साफ करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अब परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। डीडीए ने यह फैसला बायोडायवर्सिटी पार्कों के आसपास के क्षेत्रों से मिले नतीजों के बाद लिया है। डीडीए के यह प्रयास सफल रहे तो इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले वसंतकुंज स्थित संजय लेक पर किया जाएगा।

वायोडायवर्सिटी पार्क में काम करने वाले विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी पुरानी झील, नहर और तालाबों के आसपास आयुर्वेदिक किस्म के पौधे लगाकर प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्वहाल किया जा सकता है। डीडीए ने इस संबंध में मंगलवार को एक टेंडर भी जारी किया। डीडीए सूत्रों का कहना है कि वह चाहते हैं कि प्राचीन तरीकों को अपनाया जाए और ऐसे पुराने तालावो एवं झीलों को पुनर्जीवित किया जाए, जहां पानी को दूषित करने वाले जलीय जंतु समाप्त हो चुके हैं। इस तकनीक में ऐसी झीलों एवं तालाबों के आसपास औषधीय पौधों को लगाया

औषधीय पौधों एवं गाय के गोबर आदि का होगा इस्तेमाल

पहला प्रयोग वसंतकुंज की संजय लेक पर होगा

डीडीए ने विशेषज्ञ एजेंसियों से मांगे आवेदन

लगाया जाएगा। इसके साथ ही गाय से मिलने वाले पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सलाहकार मांगे गए हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों के साथ परामर्श कर सकारात्मक रास्ता निकाला जायेगा। अधिकारी का कहना है कि गाय के गोबर एवं गोमूत्र से भी दूषित पानी को साफ करने में मदद मिलने की उम्मीद है, ऐसा पर्यावरण विद मानते हैं। डीडीए के वायोडायवर्सिटी पार्क में काम करने वाले एक विशेषज्ञ ने बताया कि पुरानी झीलों एवं तालाबों के जल स्रोतों को साफ करने के लिए आसपास औषधीय पौधे लगाने से नतीजे अच्छे रहे हैं। वह यमुना एवं अरावली वायोडायवर्सिटी पार्क का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इनके आसपास पानी का स्वाद बदला है और जमीनी स्रोत भी ऊपर चढ़ा है। उनका कहना कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पानी के भीतर लगाए जाते हैं।

यह औषधीय पौधे गंदे पानी को साफ करने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि यह तरीका नीला हौज वायोडायवर्सिटी पार्क में अपनाया गया था। गंदे पानी में कुछ खास वैक्टीरिया डाले गए। इससे दूषित पानी साफ होने लगा। यह वैक्टीरियां पानी को साफ करने के साथ-साथ दूषित वैक्टीरिया को भी समाप्त करने में मदद करते हैं। यह औषधीय पौधे जलीय जंतुओं के विकास में मददगार साबित होते हैं।

Rajasthan Patrika- 24- February -2021

देवभूमि : ताकि अविरल बहती रहे जीवन धारा

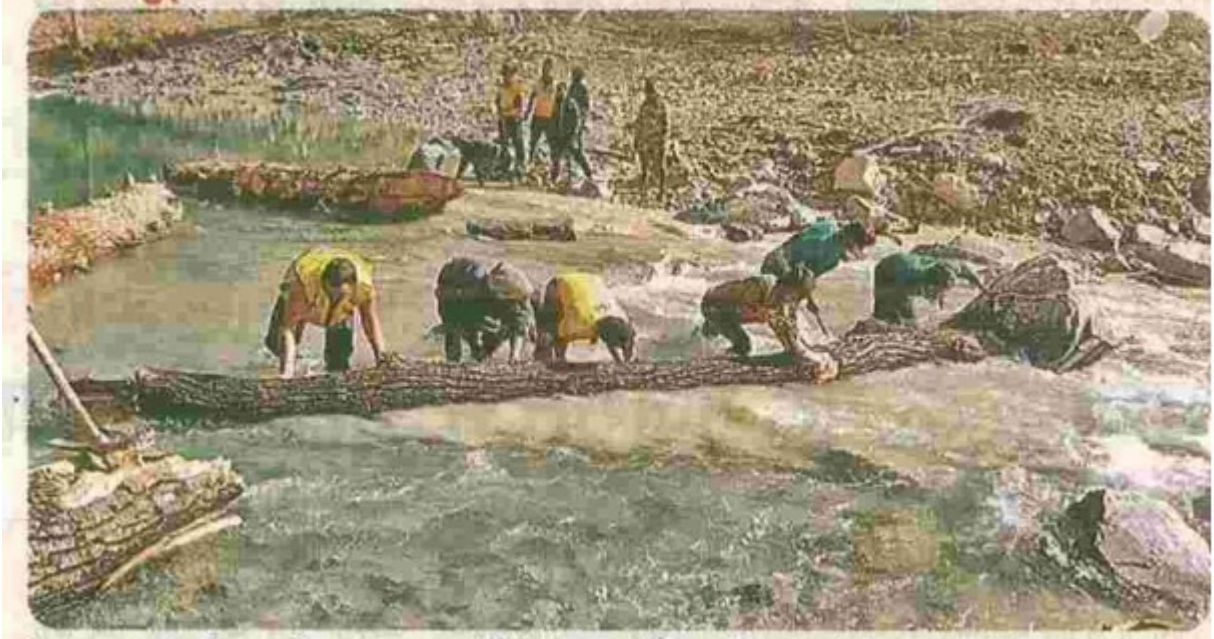

देहरादून. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के जवानों ने एसडीआरएफ व अन्य संगठनों के साथ मिलकर चमोली में ऋषि गंगा में से टूटे हुए वृक्षों को हटाया। जिससे बाधित हो रहा जल प्रवाह फिर से सुचारू हो सका।

Dainik Bhaskar- 24- February -2021

फर्रुखनगर: जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल द्वारा दिया जाएगा जल

फर्रुखनगर| जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनस्वास्थ्य एवं अभियानत्रिकी विभाग द्वारा मंगलवार को स्थानीय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में जल जीवन सांवद एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम जल एवं सीवरेज समिति, आरएमई स्टाफ तथा ग्रास रुट वर्करों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ओक्सपोर्ट कॉवेंट स्कूल की 8वीं की छात्रा कुमारी तानिया पंडित ने जल संरक्षण पर आधारित निबंध सुना कर खूब तालिया बटौरी तथा उप मंडल अभियंता ने छात्रा को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

Punjab Kesari- 24- February -2021

15 वर्षों से स्कूली छात्रों को नसीब नहीं हुआ पीने का पानी

2006 से स्कूल में नहीं पानी का कनेक्शन, स्कूल में पढ़ते है करीब 1400 छात्र

वनीता चौहान

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली सरकार का एक ऐसा स्कूल जहां बीते 15 वर्षों से छात्रों को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ है। स्कूल में वाटर कूलर तो लगे हैं लेकिन इनमें पानी नहीं है। पूरा मामला भलस्वा जे.जे कॉलोनी स्थित राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय नंबर-1 का है जहां छात्रों के लिए स्कूल में मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। इतने साल बीत जाने के बावजूद भी स्कूल में पानी का कनेक्शन नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र या तो घर से पानी लेकर आएं या फिर प्यासे ही रहें।

स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के चलते छात्र अपने घरों से पानी लेकर आते हैं। वहीं कुछ छात्र पानी खत्म हो जाने के बाद बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। सालों से स्कूल में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई की जाती थी जो कभी आता था तो कभी नहीं आता था लेकिन कोरोना के बाद से स्कूल में टैंकर से भी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या शौचालय में पानी का न होना है। बता दें कि यह स्कूल तो शिफ्ट में चलता है जिसमें करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं सुबह के समय लड़कियां और दोपहर के समय लड़के आते हैं। लेकिन दोनों सिफ्ट के बच्चों को पीने का पानी की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। बच्चों को पीने के पानी की सुविधा ना होने की वजह उन्हें अपने घरों से पानी की बोतल साथ लेकर आनी पड़ती है स्कूल के टीचर्स भी अपने लिए पीने का पानी की बोतल घर से लेकर आते हैं। या फिर वह भी पीने का पानी बाहर से मंगवाते हैं।

स्कूल में मौजूद हैं वाटर कूलर

कहने को स्कूल में वाटर कूलर लगे हुए हैं लेकिन इन में पानी का कनेक्शन न होने के चलते छात्रों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता है। स्कूल के एसएमसी मेंबर ने इस संबंध में कई बार स्कूल प्रशासन व अन्य संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दी है लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।